शुक्रवार, 9 दिसंबर 2016
लोकमत समाचार

# बड़ी कठिन है डगर देश की

गिरीश्वर मिश्र
कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
misragirishwar@gmail.com

**बाजार** की रौनक जो अतिरेक पर चल रही थी अब घट रही है. आदमी सिर्फ उपभोक्ता हुआ जा रहा था. बाजार उस के मानस पर चढ़ा हुआ था और प्रलोभन दे कर उसे अधिक से अधिक खरीदने के लिए उत्साहित किया जा रहा था. लोग बिना जरुरत चीजों को खरीदने पर आमादा हो रहे थे. खरीदना या शॉपिंग एक शगल होता जा रहा था. किसी चीज की आवश्यकता नहीं बल्कि आकर्षक पेशकश महत्वपूर्ण होने लगी थी और लोग उसमें फंसते जा रहे थे. पर राह सीधी नहीं है. अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट संभावित है. उपभोक्ताओं की मांग घटने के फलस्वरुप विज्ञापन व्यवसाय में दो हजार करोड़ का घाटा होने का अंदाजा किया जा रहा है. आशा है आर्थिक क्षेत्र में संतुलन और प्रगति के लिए और कदम भी उठाए जाएंगे. आम आदमी अच्छे दिन की आहट सुनने के लिए बेताब है. वह कष्ट सहने को भी तैयार हैं पर उसके धैर्य की भी सीमा है.

प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिया गया नोट बंदी का फैसला निश्चय ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी. इसमें संदेह नहीं कि इस आकस्मिक घटना ने जन-जीवन और व्यापार-जगत पर तात्कालिक रुप से व्यापक प्रभाव डाला. मोदीजी ने अपने इस साहसिक कदम की जरुरत और तात्पर्य को देश की जनता के सामने अपने खास अंदाज में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था. कालेधन की विकराल होती समस्या, आतंकवादियों के लिए धन की आपूर्ति तथा नकली नोटों के चलन आदि को आधार बना कर मोदीजी ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ पांच सौ और एक हजार रुपए के नोटों को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया था. कालेधन से मुक्ति और उससे प्राप्त धन का जनहित में उपयोग करने का उनका संकल्प सराहनीय है. साथ ही यह निर्णय देश में कम कैश (नकदी) वाली अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. पर इसके लिए लोग पहले से तैयार नहीं थे और अचानक लिए गए इस बड़े फैसले से भौचक्के रह गए थे. नोटबंदी का निर्णय पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था और किसी को कान में तनिक भी भनक नहीं पड़ी थी. ऐसे में इसको अमलीजामा पहनाने का तंत्र भी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं हो पाया था. कहना न होगा कि जिन प्रकट राष्ट्रीय उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में यह बड़ा जोखिम उठाया गया था वे दूरगामी प्रभाव वाले हैं. यही सोच कर आम जनता ने इस कदम को अपनी स्वीकृति दी और उसे सराहा भी.

अब नोट-बंदी को लेकर पक्ष-विपक्ष के तर्क और आरोप समाज के सामने जटिल चुनौती पेश कर रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को निर्देश दिया है कि वे अपने बैंक खातों के नवंबर आठ से इकतीस दिसंबर के बीच हुए लेन-देन के सारे ब्यौरे पार्टी अध्यक्ष को पहली जनवरी तक जरूर दे दें. राजनीति में सफाई और शुचिता की इस पहल के लिए बधाई.